राज्य विधिज्ञ परिषद् उत्तराखण्ड, नैनीताल
Bar Council of Uttarakhand, Nainital

उच्च न्यायालय परिसर मल्लीताल, नैनीताल 263001
दूरभाषः 05942–233525,मेल आई0डी0 barcounciluk@gmail.com

Latest Passport size photograph as given in Instruction No. 3, attested by the First Class Judicial Magistrate / Hon'ble Member of Bar Council of Uttrakhand

आवेदन पत्र कमांक .....सन् .....
एड़वोकेटस अधिनियम, 1961 की धारा 25 एवं तत्सम्बन्धित धारा 24 के अन्तर्गत, पंजीकरण के सम्बन्ध में।

सेवा में,

सचिव,
बार कौंसिल आफ उत्तराखण्ड,
नैनीताल।

महोदय,

प्रार्थी बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड में अधिवक्ता पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही है, अभ्यर्थी का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. मैं भारतीय नागरिक हूँ, मेरी आयु 21 वर्ष से अधिक है।
2. (क) नाम (हिन्दी में) श्री.....
3. (ख) पिता का नाम हिन्दी में) श्री .....
   (ग) माता का नाम हिन्दी में) श्रीमती.....
   (घ) निवासी.....
   .....

4. Name (In Full and Capitol Letters) As per High School Certificates Sri/Km./Smt.

5.Father's /Husband's Name (In full) Sri.

6. Mother's /Husband's Name (In full) Sri.

7. Date of Birth : DD ☐☐ **MM:** ☐☐ **YYYY:** ☐☐☐☐

8. Sex : Male: ☐ **Female:** ☐ **Third Gender:** ☐

9. Marital Status : Unmarried : ☐ **Married:** ☐ **Other:** ☐

10.Category : SC: ☐ **ST:** ☐ **OBC:** ☐ **General:** ☐

11. Resident (Specify State)

12. Permanent Address

Mobile PIN:

13. Local/Correspondance Address:

Mobile PIN:

14. Adhar Card No:

15. Email id.....

16. Rs. 500/- Noon-Judicial Stamp paper Dated .....No.

17. Intented Place of Practice: .....

Name of District Court:

Name of Subordinate Court:

Teshil:

विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व आवेदक ने इण्टरमीडिएट परीक्षा ( ) स्नातक परीक्षा ( ) परास्नातक परीक्षा ( )उत्तीर्ण की थी। कोष्ठक में जो लागू हो उसके पीछे सही (✓) का निशान लगाये।

19. Educational Qualifications : (नोटः– आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल से विधिस्नातक तक के सभी अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)

SL No.	Exam Passed	Board/ University	Name of Institute/ College	Passing year	Obtained Marks and Percentage
a.	High School				
b.	Inter				
c.	Graduation				
d.	LL.B				
e.	Any other				

(i) विधि स्नातक की उपाधि का नाम जो प्राप्त किया .....

(ii) विधि स्नातक की उपाधि व्यक्तिगत ( ) या संस्थागत ( ) परीक्षार्थी के रूप में प्राप्त किया है जैसा कि बार कौसिल ऑफ इण्डिया के नियमों में व्यवस्थित है। जो लागू हो सही (✓)का निशान लगाये।

(iii) विधि पाठ्यक्रम के अध्ययन में लगे वर्षों की संख्या .....

(vii) परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं विधि स्नातक प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की तिथि .....

20. शुल्क भुगतान करने के माध्यम पर सही (✓) का निशान लगाये, चालान ( ) डिजिटल भुगतानः– i. Yono app. ( ), ii. Phone Pay ( ), iii. G-Pay) ( ), बैंक ड्राफ्ट ( )

21. अभ्यर्थी द्वारा डिजिटल माध्यम से किये गये देय शुल्क के भुगतान का विवरणः–

(i) चालान व डिजिटल भुगतान Bar Council of Uttarakhand Rs.---------- की Transaction Id No ---------- का दिनांक .....

(ii) Bar Council of India Collection fund Account Rs.---------- की Transaction Id No---------- दिनांक.....

22. अभ्यर्थी द्वारा देय शुल्क के बैंक ड्राफ्टों का विवरणः–

(i) बार कौंसिल आफ उत्तराखण्ड पंजीकरण शुल्क की धनराशि ...../– रूपये का बैंक ड्राफ्ट नं0 .....तिथि.....

(ii) बार कौंसिल आफ इण्डिया कलेक्शन फण्ड की धनराशि...../– का बैंक का नाम ड्राफ्ट नं0 .....तिथि.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्नक–

1–

2–

3–

4–

5–

6–

7–

8–

घोषणा

मैं श्री / कुमारी / श्रीमती.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .....

उम्र .....निवासी .....बार कौंसिल आफ उत्तराखण्ड में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ / रही हूँ और निष्ठापूर्वक निम्नलिखित प्रतिज्ञा / घोषणा करता / करती हूँ कि:–

1. मैं भारतीय नागरिक हूँ।
2. मैं 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका / चुकी हूँ।
3. अपना नाम पंजीकृत होने की तिथि से उत्तराखण्ड बार कौंसिल के अधिकार क्षेत्र में नियमित रूप से विधि व्यवसाय करूँगा / करूँगी।
4. मैं शासन अथवा किसी अन्य विभाग में सेवारत कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं हूँ।
5. मैं कोई अन्य व्यापार अथवा कारोबार नहीं करता / करती हूँ।
6. भारत की किसी राज्य की बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ता पंजीकरण का मेरा आवेदन पत्र कभी अस्वीकार नहीं किया गया है ना ही मैंने भारत की किसी अन्य बार कौंसिल में इससे पूर्व पंजीकरण हेतु आवेदन किया, यदि किया हो तो उसका विवरण अलग से शपथ पत्र पर उल्लेखित करूंगा।
7. मैं घोषणा कर रहा / रही हूँ कि मैं अपनी योग्यता सामर्थ्य व कर्तव्यनिष्ठा से एक अधिवक्ता के रूप में कार्य एवं व्यवहार को वस्तुतः ईमानदारी से निर्वाह करूँगा / करूँगी और पंजीकृत अधिवक्ताओं का व्यवहार विनियमित करने के लिए लागू न्यायालयों द्वारा भविष्य में जारी किये गये आदेशों एवं बार कौंसिल द्वारा बनाये गये नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा / करूँगी।
8. मैं घोषित करता / करती हूँ कि भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा रखूँगा / रखूँगी।
9. मैं घोषित करता / करती हूँ कि मैं किसी सेवा में युक्त होने, व्यापार, कारोबार अथवा अन्य वृत्ति करने पर अपना अधिवक्ता प्रमाण–पत्र बार कौंसिल को प्रेषित कर सर्मपण कर दूँगा / दूँगी।
10. मैं घोषित करता / करती हूँ कि विधि व्यवसाय के अपने साधारण स्थान अथवा उसके परिवर्तन की सूचना बार कौंसिल को दूँगा / दूँगी।
11. मैं घोषित करता / करती हूँ कि मेरे विरूद्ध नैतिक नीचता और भारतीय दंड / न्याय संहिता अथवा अन्य किसी एक्ट का कोई अपराधिक मुकदमा किसी भी फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही किसी आपराधिक केस में मेरी गिरफ्तारी हुई है, मेरे विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई विवेचना नहीं चल रही है। (यदि हां तो उसका विवरण शपथ पत्र पर दे)
12. मैं घोषित करता / करती हूँ कि अधिवक्ता के रूप में बार कौंसिल द्वारा पंजीकृत किये जाने के बाद मेरे विरूद्ध (Moral Turpitude) के अन्दर आने वाला अपराध और कोई भी अन्य आपराधिक वाद या एफ0आई0आर0 कायम होता है तो मैं उपरोक्त अपराधिक वाद से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिर्पोट या यदि परिवाद कायम होता है या किसी न्यायालय द्वारा मुझे किसी आपराधिक मामलें में दोषी साबित किया जाता है तो उक्त की सूचना उत्तराखण्ड बार कौंसिल को, उक्त तथ्य की जानकारी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दूँगा / दूँगी इस बात को सुनिश्चित करूँगा कि परिवाद या एफ0आई0आर0 की प्रति बार कौंसिल को मिल गई है।
13. मैं घोषित करता / करती हूँ कि अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के पश्चात मैं अपने जीवन यापन हेतु वकालत के साथ किसी अन्य व्यवसाय या नौकरी या अन्य प्रोफेशन को जीविकापार्जन के साधन के रूप में नही अपनाऊँगा / अपनाऊँगी।
14. मैं घोषित करता / करती हूँ कि मैंनै बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्मित खण्ड 6 में वर्णित चैप्टर 1 से चैप्टर 4 में दिये (पंजीकरण फार्म के साथ संलग्न) समस्त नियमों का भली–भाँति अध्ययन कर लिया है जिनका पालन पंजीकरण के बाद पूरी निष्ठा के साथ नियमित रूप से करूँगा / करूँगी।
15. मैं घोषित करता / करती हूं कि मेरे द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र में दी गयी सूचनायें और उसके साथ संलग्नक समस्त दस्तावेज और शैक्षिक प्रमाण पत्र / सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की है, वे सभी पूर्णतया सही व सत्य हैं। यदि वे गलत पाये जाते हैं तो बार कौंसिल उत्तराखण्ड को यह अधिकार होगा कि वह पंजीकरण निरस्त कर दें और अन्य कार्यवाही करने के लिये बार काउन्सिल उत्तराखण्ड स्वतन्त्र है।

सत्यापन

मैं घोषित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा पत्र के पद संख्या 1 से 15 में दी गई समस्त सूचना मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही व सत्य है इसमें न कुछ छिपाया गया है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

चरित्र प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री .....
पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री .....को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये सच्चरित्र हैं और अधिवक्ता पंजीकरण होने योग्य एवं उपयुक्त हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
पदवी
अधिवक्ता पंजीकरण संख्या

कार्यालय का प्रतिवेदन (अभ्यर्थी कॉलम स्वयं भरें)

आवेदक श्री .....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
विश्वविद्यालय .....
के विधि स्नातक हैं तथा इस प्रकार ये सन् 1961 ई0 के एडवोकेट्स अधिनियम की धारा 24(1) खण्ड डी के उपलब्ध 1 के अन्तर्गत अधिवक्ता होने के अधिकारी हैं।

पंजीकरण लिपिक

प्रतिवेदन

सन् 1961 के एडवोकेट्स अधिनियम की धरा 24 के अन्तर्गत आवेदक को एक अधिवक्ता पंजीकृत कर लिया जाये।

तिथि .....

सचिव

पंजीकरण समिति का आदेश

(1)आवेदक श्री .....
पुत्र/पत्नी/पत्नी श्री.....का नाम सन् 1961 ई0 के एडवोकेट्स अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत अधिवक्ता पंजीकरण कर लिया जाये/न किया जाये।
दिनांक .....

अन्य टिप्पणी–

.....	.....	.....
सदस्य	सदस्य	सदस्य

पंजीकरण प्रमाण–पत्र तैयार करने की तिथि .....
पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या.....

हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्ता

आवश्यक निर्देश एवं शुल्क विवरण

1. पंजीकरण फार्म अभ्यर्थी आनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
2. पंजीकरण फार्म के साथ शुल्क का भुगतान चालान, डिजिटल पेमेन्ट (अभ्यर्थी के स्वयं के खाते से किया गया भुगतान ही मान्य होगां) अथवा बैंक ड्राफ्ट, के माध्यम से जमा करें।
3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) नं0 352/2023 गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 के अनुपालन में पंजीकरण शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है–

(अ)– सामान्य व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के लिए रूपये 600/– **Bar Council of Uttarakhand, Nainital** के मद में तथा रूपये 150/– **Bar Council of India Collection Fund Account, Nainital** के मद में।

(ब)– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए रूपये 100/– **Bar Council of Uttarakhand, Nainital** के मद में तथा रूपये 25/– **Bar Council of India Collection Fund Account, Nainital** के मद मे देय होगा। सभी ड्राफ्ट एस0बी0आई0 हाईकोर्ट ब्रान्च नैनीताल के पक्ष में देय हो।

नोटः– डिजिटल भुगतान के लिए खाता सख्या व आई0एफ0एस0सी0 कोड निम्नवत् हैः–

(1) बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड नैनीताल का खाता संख्या 30612293272, IFSC Code No. SBIN0010634 है।

(2)बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, कलेक्शन फण्ड एकाउन्ट का खाता संख्या 30602947546 भारतीय स्टेट बैंक शाखा उच्च न्यायालय, मल्लीताल, नैनीताल, IFSC Code No. SBIN0010634 है।

4. फार्म जमा होने के पश्चात् एक माह के भीतर विधि स्नातक प्रमाण–पत्र/अंकपत्र संबंधित विश्वविद्यालय को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना प्रार्थी को प्रेषित की जायेगी, विश्वविधालय को देय सत्यापन शुल्क प्रार्थी स्वंय विश्वविधालय में जमा कर विश्वविधालय के माध्यम से सत्यापन बार कौंसिल कार्यालय को प्रेषित करवायें। अंकतालिका का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा डाक या ई–मेल के माध्यम से बार कौंसिल कार्यालय को प्रेषित ही मान्य होगे अन्य किसी माध्यम से प्रेषित सत्यापन रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 12.06.2010 के उपरान्त विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जायेगा जो दो वर्ष हेतु वैध एवं मान्य होगा।
6. दो वर्ष में प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिनका अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, वो ऑल इण्डिया बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण करेंगे तत्पश्चात् ही स्थायी पंजीकरण प्रदान किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में देश–प्रदेश के न्यायालयों को सूचना प्रेषित की जायेगी कि अमुक अभ्यर्थी का अस्थायी पंजीकरण समाप्त हो चुका है व स्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी अधिवक्ता व्यवसाय करने योग्य नहीं है।
7. स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही सी0ओ0पी0 के लिये आवेदन मान्य होगा और उस समय वांछित शुल्क लिया जायेगा।
8. अभ्यर्थी को अपने आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, यदि अभ्यार्थी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी नहीं है तो उसे उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने का कोई पहचान/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9. आवेदन प्रपत्र पर प्रत्येक पृष्ट के नीचे और निर्दिष्ट सभी उपयुक्त स्थानों पर आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
10. आवेदन पत्र के साथ संलग्नक इस क्रम में लगायेः– शुल्क भुगतान के चालान की प्रति/डिजिटल भुगतान की स्लिप/ड्राफ्ट, शपथ–पत्र, सादे पन्ने पर चार पासपोर्ट फोटो, हाईस्कूल– अंक तालिका, प्रमाण– पत्र, इण्टरमीडिएट– अंक तालिका, प्रमाण– पत्र, स्नातक– अंक तालिका, डिग्री और विधि (एल0एल0बी0) फाइनल एवं समस्त षटमासिक/वार्षिक परीक्षाओं की अंक तालिका, डिग्री की स्व प्रमाणित छाया प्रति एवं अंत में रू0 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के क्रम में संलग्न करें स्नातक एवं विधि स्नातक के मूल प्रमाण पत्र न हों तो अंत कालीन प्रमाण–पत्र (जो कि प्रमाण–पत्र निर्गत होने की तिथि से 6 माह तक वैध होते हैं) की मूल प्रति संलग्न करें।
11. यदि आवेदक कभी नौकरी में रहा हो तो सेवा निवृत्ति (रिटायरमेन्ट), त्याग पत्र अथवा उन्मुक्ति (डिसचार्ज) के कारण नौकरी छोड़ने का मूल प्रमाण पत्र अधिकारीगण की मोहर सहित संलग्न कीजिए।
12. अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की प्रति पंजीकरण आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्नक करें।
13. नोटरी द्वारा प्रमाणित टाइपशुदा शपथ पत्र दस रूपये के स्टाम्प पत्र पर होना चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप इस पृष्ठ के दूसरी ओर अंकित है। शपथ पत्र में विश्राम वर्ष का कारण सहित स्पष्ट उल्लेख करें। बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के सर्कुलर पत्रांक संख्या BCI:D:4657/2026 दिनांक 17.07.2026 के अनुपालन में नोटरी द्वारा प्रमाणित टाइपशुदा शपथ पत्र दस रूपये के स्टाम्प पत्र पर होना चाहिए। प्रारूप आवेदन प्रपत्र के पृष्ठ संख्या 8A, 8B है।
14. नोटरी द्वारा प्रमाणित टाइपशुदा शपथ पत्र दस रूपये के स्टाम्प पत्र पर होना चाहिए।
15. रू0 500/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर संलग्न करें।
16. आवेदन पत्र में चिपकायी गयी फोटो जो सफेद शर्ट, काली टाई व काले कोट या बन्द गले का कोट या शेरवानी में तथा महिलाओं हेतु सफेद साड़ी एवं काले कोट हो तथा किसी प्रथम श्रेणी के मजि0/जज अथवा बार कौंसिल के निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इस फोटो के अतिरिक्त 4 फोटो एक सफेद कागज पर नत्थी करें।
17. चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रथम श्रेणी के मजि0, जज, बार कौंसिल आफ़ उत्तराखण्ड के निर्वाचित सदस्य अथवा दस वर्ष से अधिक अवधि के पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि चरित्र प्रमाण पत्र अधिवक्ता द्वारा दिया गया हो तो उनके नाम, पूर्ण हस्ताक्षर तथा पंजीकरण की संख्या का स्पष्ट उल्लेख हो।
18. अभ्यर्थी स्वपता लिखा हुआ 10X12 इंच का एक लिफाफा जिस पर 65 रूपये मूल्य के डाक टिकट लगा हो, और 4x8 इंच का एक स्वपता लिखा लिफाफा जिस पर 60 रूपये मूल्य के डाक टिकट लगा हो, फार्म के साथ संलग्न कर प्रेषित करें।
19. पंजीकरण के पश्चात अधिवक्ता उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, देहरादून द्वारा संचालित ''अधिवक्ता भविष्य निधि योजना'' और बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड स्टेब्लिसमेन्ट फण्ड की सदस्यता हेतु आवेदन करें। योजना का लाभ उठायें।
20. आवेदन पत्र के साथ संलग्न Extract of *relevant rules* framed by the Bar Council of India (As amended upto31st July 1995) बार कौंसिल की बेबसाइट पर अध्ययन हेतु अपलोड़ है ।

नोट–माह के प्रत्येक रविवार एवं द्वितीय शनिवार तथा राजकीय अवकाश के दिन कार्यालय बन्द रहेगा।

सचिव

स्टेट बार कौंसिल आफ उत्तराखण्ड

शपथ–पत्र (प्रारूप)

समक्ष बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड, नैनीताल।

नोटः– किसी भी प्रकार के विश्राम वर्ष का शपथ–पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें। यदि हाईस्कूल से लेकर फार्म जमा करने की तिथि तक अनुत्तीर्ण या कही प्रवेश न लिया हो तो उसका भी उल्लेख करें। कृपया शपथ पत्र टाईप करवाये इस प्रारूप पर भरा/लिखा हुआ शपथ पत्र मान्य नहीं है।

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....यह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि

1. यह कि मैं जन्म से भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह कि मेरी जन्म तिथि .....है और मेरी आयु 21वर्ष से अधिक है।
3. यह कि मैं कभी किसी अपराध में दण्डित नही हुआ हूँ।
4. यह कि मेरे विरूद्ध नैतिक कदाचार, भारतीय दण्ड/न्याय संहिता अथवा अन्य किसी एक्ट का कोई आपराधिक मुकदमा किसी भी फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन नही है और न ही किसी अपराधिक केस में मेरी गिरफ्तारी हुई न ही मेरे विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई विवेचना चल रही है। (यदि किसी अपराध का कोई मुकदमा पुलिस अथवा न्यायालय में विचाराधीन हो तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए)
5. यह कि मै इस समय किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत नही हूँ।
6. यह कि मैं कभी किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत नही था (यदि प्रार्थी किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत रहा है तो उसका विवरण दें और जिस स्थान पर रहा है, वहाँ सेवायोजन का चरित्र प्रमाण–पत्र दें तथा यह भी स्पष्ट करे कि सेवा समाप्ति का कारण क्या था)।
7. यह कि मैंने इससे पूर्व किसी स्टेट बार कौंसिल अथवा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र नही दिया है और न ऐसा कोई प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत हुआ।
8. यह कि मैंने हाईस्कूल परीक्षा सन् ..... में उत्तीर्ण की है।
9. यह कि मैंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा सन्..... में उत्तीर्ण की है।
10. यह कि मैंने स्नातक की परीक्षा सन् ..... में उत्तीर्ण की है।
11. यह कि मैंने विधि स्नातक की परीक्षा सन् ..... में उत्तीर्ण की है।
    (यदि हाईस्कूल से लेकर आवेदन पत्र देने की तिथि तक की अवधि में प्रार्थी का किसी वर्ष विश्राम हो अथवा अनुत्तीर्ण हुआ हो तो उसका स्पष्टीकरण शपथ पत्र में उल्लिखित करें।)
12. यह कि मेरे हाईस्कूल प्रमाण–पत्र से लेकर विधि स्नातक के प्रमाण पत्र तक मेरे नाम तथा सरनेम में कोई विभिन्नता नही है।
    (यदि हाईस्कूल से लेकर विधि स्नातक के प्रमाण–पत्रों में किसी प्रकार नाम की विभिन्नता है तो प्रार्थी इस सम्बन्ध में इस आशय का स्पष्टीकरण दे कि हाईस्कूल से लेकर विधि स्नातक सभी प्रमाण–पत्र उसी से ही सम्बन्धित हैं।
13. यह कि अधिवक्ता के रूप में स्टेट बार कौंसिल द्वारा पंजीकृत किये जाने के बाद मेरे विरूद्ध Moral Turpitude के अन्दर आने वाला और अन्य कोई भी अपराधिक वाद या एफ0आई0आर0 कायम होता है तो मैं उपरोक्त अपराधिक वाद से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिर्पोट या कोई परिवाद कायम होता है अथवा शपथकर्ता को किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो उपरोक्त की सूचना उत्तराखण्ड बार कौंसिल को उक्त तथ्य की जानकारी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर पंजीकृत डाक से प्रेषित कर दूंगा/दूँगी। इस बात को सुनिश्चित करूंगा/करूंगी कि मेरे द्वारा प्रेषित सूचना बार कौंसिल कार्यालय को मिल गई है।
14. यह कि अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के पश्चात मैं अपने जीवन यापन हेतु वकालत के साथ किसी अन्य व्यापार, व्यवसाय या नौकरी या अन्य प्रोफेशन को जीविकोपार्जन के साधन के रूप में नही अपनाऊँगा ।
15. यह कि शपथकर्ता अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के बाद एक ही बार एशोसियेशन में अपने मत का प्रयोग करते हुये One Bar One Vote के नियम का पालन करूंगा/करूँगी।
16. यदि कोई विशेष उल्लेख हो तो उसका विवरणः–

सत्यापनः–

यह कि शपथ–पत्र के पद संख्या 1 से पद संख्या 16 तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास में सही व सत्य है, इसमें कोई भी बात झूठ नही है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है। भगवान मेरी सहायता करे।

आज दिनांक ..... स्थान .....पर सत्यापित किया।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

ANNEXURE A

FINAL STANDALONE SWORN AFFIDAVIT AT THE STAGE OF ENROLMENT

Derivation note. This affidavit records awareness of duties already traceable to the Preamble to Chapter II, Part VI, Rules 1, 2, 4, 5, 7, 17, 24, 36 and 37 of the Bar Council of India Rules. It is declaratory, educative and evidentiary. It shall not by itself operate as an additional ground to refuse, defer or deny enrolment, Sanad or licence to practise beyond the Advocates Act, 1961 and validly notified Rules.

Who shall fill this annexure

Every candidate seeking enrolment as an Advocate with the concerned State Bar Council.

Stage at which this annexure shall be executed

At the time of the enrolment process, as a standalone declaration for record, awareness and future professional responsibility, without creating any additional substantive eligibility condition beyond the Advocates Act, 1961 and the rules validly framed thereunder.

I, _____, son/daughter/spouse of _____, aged about _____ years, resident of _____, presently seeking enrolment as an Advocate with the Bar Council of _____, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I have read and understood the Bar Council of India Circular/Circular regarding maintenance of dignity, restraint and professional ethics in the use of social media by Advocates, law students and interns, including the provisions relating to reels, short videos, Court premises, Court proceedings, chambers, judicial hearings, live-streamed proceedings, professional work, AI generated content, deepfake videos, voice cloned audio and synthetic digital content.

2. That I undertake to maintain dignity, restraint, confidentiality and professional responsibility in all digital and social media conduct connected with Courts, Judges, counsel, litigants, witnesses, victims, clients, chambers, Court proceedings, professional work and the legal profession.

3. That I shall not create, upload, publish, circulate, forward, repost, monetise or use any reel, short video, edited clip, meme, dramatic presentation, promotional post, AI generated image, deepfake video, voice cloned audio, face swapped visual, synthetic avatar, manipulated screenshot or synthetic content depicting or purporting to depict any Judge, Court, Tribunal, counsel, litigant, witness, victim, client, Court officer, Court proceeding, chamber discussion or professional interaction in a false, misleading, mocking, sensational, scandalising, defamatory, privacy invasive, confidential or professionally improper manner.

4. That I shall not record, photograph, publish or circulate any Court proceeding, virtual hearing, client conference, chamber discussion, case file, cause list, pleading, draft, research note, case strategy, settlement discussion, mediation material or professional communication except

where expressly permitted by law, Court rules and professional ethics.

5. That I shall not use robes, bands, Court premises, Court corridors, chamber settings, senior chambers, law firm spaces, client files, Court signage or the identity of being an Advocate for indirect advertising, solicitation, sensationalisation, glamourisation, follower seeking, personal branding or content inconsistent with the dignity of the profession.

6. That I understand that ordinary personal freedom of expression is not prohibited, but that such freedom cannot be used to lower the dignity of Courts, breach confidentiality, misuse professional identity, solicit work, invade privacy, mislead the public or prejudice the administration of justice.

7. That I understand that breach of this undertaking may be considered in accordance with the Advocates Act, 1961, the Bar Council of India Rules, Court rules, applicable law and principles of natural justice.

Verification

Verified at _____ on this _____ day of _____, 20____ that the contents of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Deponent

Extract of *relevant rules* framed by the Bar Council of India
(As amended upto31st July 1995)
PART-VI
RULES GOVERNING ADVOCATES
CHAPTER-I
RESTRICTIONS ON SENIOR ADVOCATES

(Rules under Sections 16 (3) *and* 49 *(l) (g) of the Act)*

Senior Advocates shall in the matter of their practice of the. profession of law mentioned in Section 30 of the Act, be subject to the following restrictions:

(a) A Senior Advocate shall not file a vakalatnarna or act in any Court, or Tribunal, or before any person or other authority mentioned in Section 30 of the Act.

Explanation: "To Act" means to file an appearance or any pleading or application in any court, to Tribunal or before any person or other authority mentioned in Section 30 of the Act. or to do any act other than pleading required or authorised bylaw to be done by a party in such Court, or Tribunal, or before any person or other authority mentioned in the said Section either inperson or by his recognised agent or by an advocate or an attorney on his behalf

(b) (i) A Senior Advocate shall not appear without an Advocate on Record in the Supreme -Court or without an Advocate in Part II of the State Roll in any court, or Tribunal, or before any person or other authorities mentioned in Section 30 of the Act.

(ii) Where a Senior Advocate has been engaged prior to the coming into force to the Rule in this Chapter, he shall not continue thereafter unless an Advocate in Part II of the State Roll is engaged along with him. Provided that a Senior Advocate may continue to appear with cut an Advocate in Part II of the State Roll' in cases in which he had been briefed to appear for the prosecution or the defence in a criminal case, if he was so briefed before he is designated as a senior Advocate or before coming into operation of the rules in this Chapter as the case may be

(c) He shall not accept instructions to dtaftpleadinq or affidavits, advice on evidence or to do any drafting work of an analogous kind in anyCourt or-Tribunal, or before any person or other authority mentioned in Section 30 of the Act or undertake convincing work of any kind whatsoever. This restriction however shall not extend to setting any such matter as aforesaid in consultation with an Advocate in Part II or the State Roll.

(cc) A Senior Advocate shall, however, be free to make concessions or give undertakings in the course of arguments on behalf of his clients on instructions from the junior advocate.

(d) He shall not accept directly from a client any brief of instructions to appear in any Court or Tribunal, or before any person or other authority in India .

(e) A Senior Advocate who had acted as Advocate (Junior) in case, shall not after he has been designated as a Senior Advocate advise on grounds of appeal in a Court of Appeal or in the Supreme Court, except with an Advocate as aforesaid.

(f) A Senior Advocate may. in recognition of the services rendered by an Advocate in Part" of the State Roll appearing in any matter pay him a fee which he considers reasonable

CHAPTER-II
Standards of Professional Conduct and Etiquette

(Rules under Section 49 (1) *(c) of the Act read with the Proviso thereto)*

Preamble

An advocate shall, at all times, comport' himself in a manner befitting his status as an officer of the Court, a privileged member of the community. and a gentleman. bearinqin mind thaf what may be lawful and moral for a perso: who is not a member of the Bar, or for a member of the Bar in his non-professional capacity may still b s improper for an Advocate. Without prejudice to the generality of the foregoing obligation, an Advocate shall feariessiy uphold the interests of his client, and in his conduct conform to the rules hereinafter mentioned both in letter and in spirit. The rules hereinafter mentioned contain of conduct and etiquette adopted as general guides; yet the specific mention there of shall not be construed as a denial ottne existence of other equally imperative though not specifically mentioned.

Section I- Duty to the Court .

1: An Advocate Shall, during the presentation of his case and while oinerwise acting before a Court, conduct himself with dignity and self-respect. He shall not be servile and whenever there is proper ground for serious complaint against judicial officer, it shall be his right and duty to submit his grievance to proper authorities.

2. An Advocate shall maintain towards the Courts' a respectful attitude, bearing in mind that the dignity of the judicial office is' essential for the survival of free community.

3. . An Advocate shall not influence the decision of a Court by any ili2galor improper means Private communications with ajudge relating to a pending case are forbidden.

4. An Advocate shall use his best efforts to restrain and prevent his client from resorting to sharp or unfair practices or from doing anything in relation to the court, opposing counselor parties which the Advocate himself ought not to do. An advocate shall refuse to represent the client who persists in such improper conduct. He shall not consider himself a more mouth-piece of the client and shall exercise his own judgment in the use of restrained language in correspond dence, avoiding scurrilous attacks in pleadings. and using intemperate language during arguments in Court.

5. An Advocate shall appear in court at all times only in the prescribed dress, and his appearance shan always be

presentable.·

6 An Advocate shall not enter appearance, act, plead or practise in any way before a Court, Tribunal or Authority mentioned in Section 30 of the Act, if the sole or any member thereof is related to the Advocate as father, grandfather, son, grand-son, uncle, brother, nephew, first cousin, husband, wife, mother, daughter sister. aunt, niece, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, brother-in-law, daughter-in-law or sister-in-law.

7. For the purposes of this rule, Court shall mean a Court, Bench or tribunal in which above mentioned relation of the advocate is a judge, Member or the Presiding Officer.

9. An Advocate shall not wear bands or gown in public places other than in Courts except on' such ceremonial occasions and at such places as the Bar Council of India or the Court may prescribe. An Advocate shall not appear in or before any Court or Tribunal or any other authority for or against an organisation or an institution, society or corporation, if he is a member of the Executive Committee of such organistion or institution or society· or corporation. "Executive Committee", by whatever name it may be called, shall include any Committee or body of persons which, for the time being, is vested with the general management of the affairs of the organisation or institution, society or corporation. Provided that this rule shall not apply to such a member appearing as "amicus curiae" or without a fee on behalf of a Bar Council, Incorporated Law Society or a Bar Association.

10. An Advocate should not act or plead in any matter in which he is himself peculiarly interested.

Illustration:

I. He should not act in a bankruptcy petition when he himself is also a creditor of the bankrupt.

II. He should not accept a brief from a company of which he is Director. An Advocate shall not stand as a surety, or certify the soundness of a surety for his client required for the purpose of any legal proceedings.

Section II Duty to the Client

11. An Advocate is bound to accept any brief in the Courts or Tribunals or before any other authority in or before which he proposes to practice fee consistent with his standing at the Bar and the nature of the case. Special circumstances may justify hi? refusal to accept a particular brief.

12. An Advocate shall not ordinarily withdraw from engagements, once accepted, without sufficient cause and unless reasonable and sufficient notice is given to the client. Upon his withdrawal from a case, he shall refund such part of the fee as has not been earned.

13. An Advocate should not accept a brief or appear in a case in which he has reason to believe that he will be a witness, and if being engaged in a case, it becomes apparent that he is awitness on a material question of fact, he should 'not continue to appear as an Advocate if he can retire without jeopardising his client's interests. . An

14. Advocate shall, at the commencement of his engagement and during the continuance thereof, make all such full and frank disclosures to his client relating to his connection with the parties and any interest in or about the controversy as are likely to affect his client's judgement in either engaging him or continuing the engagement.

15. It shall be the duty of an Advocate fearlessly to uphold the interests of his client by all fair and honourable means without regard to any unpleasant consequences to himself or any other. He shall defend a person accused of a crime regardless of his personal opinion as to the guilt of the accused, bearing in mind that his loyalty is to the law which requires that no man should be convicted without adequate evidence.

16. An Advocate appearing for the prosecution of a criminal trial shall so conduct the prosecution that it does not lead to conviction of. The innocent. The suppression of material capable of establishing the innocence of the accused shall be scrupulously avoided

17. An Advocate shall not, directly or indirectly, commit a breach of the obligations imposed by Section 126 of the Indian Evidence Act.

18. An Advocate Shall not, at any time, be a party to fomenting of litigation.

19. An Advocate Shall act on the instructions of any person other than his client or his authorised agent.

20. An Advocate shall not stipulate for a fee contingent on the results of litigation or agree to share the proceeds thereof.

21. An Advocate shall not buy or traffic in or stipulate for or agree to receive any share or interest in any actionable claim. Nothing in this rule shall apply to stock, shares and debentures of government securities, or to any instruments which are, for the time being by law or custom, negotiable or to any mercantile document of title to goods

22. An Advocate shall not, directly or indirectly, bid for or purchase, either in his own name or in any other name, for his own benefit or for the benefit of any other person, any property sold in the execution of a decree or order in any suit, appeal or other proceeding in which he was in any way professionally engaged. This prohibition, however, .does not prevent an Advocate from bidding for or purchasing for his client any property which his client may himself legally bid for or purchase, provided the Advocate is expressly authorised in writing in this behalf.

23. An Advocate shall not adjust fee payable to him by his client against his own personal liability to the client, which liability does not arise in the course of his employment as an Advocate.

24 An Advocate shall not do anything whereby he abuses or takes advantage of the confidence reposed in him by his client.

25. An Advocate should keep accounts of the client's money entrusted to him, and the accounts should show the amounts received from the client or on his behalf, the expenses incurred for him and debits made on account of fees with respective dates and all other necessary particulars

26. Where moneys are received from or on account of a client, the entries in the accounts should contain a reference

as to whether the amounts have been received for fees or expenses, and during the coursed the proceedings no Advocate shall, except with the consent in writing of the client concerned. be at liberty to divert any portion of the expenses towards fees.

27. Where any amount is received or given to him on behalf of his client; the fact of such receipt must be intimated to the client, as early as possible.

28 After the termination of the proceeding, the Advocate shall be at liberty to appropriate towards the settled fee due to him, any sum remaining unexpended out of the amount paid or sent to him for expenses, or any amount that has come into his hands in that proceeding

29. Where the fee has been left unsettled, the Advocate shall be, entitled to deduct, out Of any moneys of the client remaining in his hands, at the termination of the proceeding for which he had been engaged the fee payable under the rules of the Court, in force for the time being, or by then settled and the balance, if any, shall be refunded to the client .

30. A copy of the client's account shall be furnished to him on demand provided the necessary copying charge is paid.

31. An Advocate shall not enter into arrangements whereby funds in his hands are converted into loans.

32. An Advocate shall not lend money to his client for the purpose of any action or legal proceedings in which he is engaged by such client .

Explanation. An Advocate shall not be held guilty for a breach of this rule, if in the course a pending suit or proceeding, without any arrangement with the client in respect of the same, the Advocate feels compelled by reason of the rule of Court to make a payment to the court on account of the client for the progress of the suitor proceeding

33. An Advocate who has, at any time advised in connection with the institution of a suit. appeal or other matter or has drawn pleadings, or acted for a party, shall not act, appear or plead for the opposite party.

Section III-Duty to Opponent

34. An Advocate shall not in any way communicate or negotiate upon the subject matter of controversy with any party represented by an Advocate except through that Advocate.

35. An Advocate shall do his best to carry out legitimate promises made to the opposite party even though not reduced to writing or enforceable under the rules of the Court.

Section IV-Duty to Colleagues

36. An Advocate shall not solicit work or advertise, either directly or indirectly, whether by circulars, advertisements, touts, personal. communication, interviews not warranted by personal relations, furnishing or newspaper inspiring comments or producing his photograph to be published in connection with cases in which he has been engaged or concerned. His sign-board or name-plate should be of a reasonable size. The sign-board or name-plate or stationery should not indicate that he is or has been President or Member of a Bar Councilor of any Association or that he has been associated with any person or organization or with any particular cause or matter or the specialises in any particular type of work or that he has been a judge or an advocate general.

37. An Advocate shall not permit his professional services or his name to be used in aid of or to make possible, the unauthorised practice of law by any agency.

38. An Advocate shall not accept a fee less than the fee taxable under the rules when the client is able to pay the same.

39. An Advocate shall not enter appearance in any case in which there is already a vakalat or memo of appearance filed by an Advocate engaged for a party except with his consent; in case such consent is not produced he shall apply to the Court stating reasons why the said consent should not be produced and he shall appear only after obtaining the permission of the Court.

Section IV-A

40. Every Advocate borne on the rolis of the State Bar Council shall. pay to the State Bar council a sum of Rs. 90/- every third year commencing from 1 stApril, .1993 along with a statement of particulars as given in the form set out at the end of these Rules, the first payment to be made on or before 1 st April, 1993 or such extended time as notified by the Bar Council of India or the concerned State Bar Council.

Provided further however that an advocate shall be at liberty to pay in lieu of the payment of Rs. 90/- every three years a consolidated amount of Rs. 300/- .. This will be a life time payment to be kept in the fixed deposit by the concerned State Bar Council and interest to be used or the purpose of the rule. However, payment made by the concerned Advocate before this consolidated payment shall be exclusive of it and no credit shall be given for the payment, but those advocates who have paid consolidated am out of Rs. 200/- only as a consolidated, Rs. 100/-will be required to pay.

Explanation 1 : Statement of particulars as required by rule 40 in the form set out shall require to be submitted only once in three years.

Explanation 2 : All Advocates who are in actual practice and not drawing salary or not in full time service and not drawing any from their respective employers are only required to pay the amount referred to in this rule.

Explanation 3 : This rule will be effectives from 1.4.1994 and for period prior to this Advocates will continue to be covered by old Rule.

41. (1) All the sums so collected by the State Bar Council in accordance with Rule 40 shall be credited in a separate fund known as "Bar Council of India Advocates Welfare Fund for the State" and shall be deposited in the bank as

provided hereunder.

(2) The Bar Council of India Advocates Welfare Fund Committee for the State shall remit 20% of the total amount collected and credited to its account, to ~he Bar Council of India by the end of every month which shall be credited by the Bar Council of India and the Bar Council of India shall deposit the said amount in a separate fund to be known as "BAR COUNCIL OF INDIA ADVOCATES WELFARE FUND". This fund shall be managed by the Welfare Committee of the Bar Council of India in the maimer prescribed from time to time by the Bar Council of India for the Welfare of the Advocates.

(3) This rest 80% of the total sum so collected by the Bar Council of India Advocates Welfare Find Committee for the State under Rule 41 (1) shall be utilised for the welfare of advocates in respect of Welfare Schemes sponsored by the respective State Bar Councils and this fund.sha'! be administered by the Advocates Welfare Committee for the State Which shall submit its report annually to the Bar Council of India.

42. If any advocate fails to pay the aforesaid sum within the prescribed time as provided under rule 40, the Secretary of the. State Bar-Council shall issue to him a notice to show cause within a month why his right to practice be not suspended. In case the advocate does not pay the amount or fails to show sufficient cause, a Committee of three members constituted by the State Bar'Council in this behalf may pass an order suspending the right of the advocate to practise. Provided that the order of suspension shall cease to be in force when the advocate concerned pays the amount along with a late. fee of Rs. 50/- and obtain a certificate in this behalf from the .State Bar Council.

43. An advocate who has been convicted of an offence mentioned under section 24A of the Advocates Act or has been declared insolvent or has taken full time service or part time service or engages in business or any avocation
inconsistent with his practising as an Advocate or has incurred any disqualification mentioned in the Advocates Act or the rules made thereunder, shall send a declaration to that effect to the respective State Bar Council in which the Advocate is to show sufficient cause for not filling such declaration provided therefore the Committee constituted by the State Bar Council under rule 42 may pass orders suspending the right of the advocate to practise.
Provided that it shall be open-to the Committee to condone the delay on an application being made in this behalf. Provided further that an advocate who had after the date of his enrolment and before the coming into force of this
rule, become subject to any of the disqualifications mentioned in this rule, shall within a period of ninety days of the coming into force of this rule send declaration referred to in this rule to the respective State Bar Council in which the Advocate is enrolled and on failure to do so by such Advocate all the provisions of this rule would apply.

44. An appeal shall lie to the Bar Council of India at the instance of an aggrieved advocate within a period of thirty days from the date of the order passed under rules 42 and 43.

44A. (1) There shall be a Bar Council of India Advocates welfare Committee. consisting of five members elected from amongst the members of the Council. .The term of the members of the committee shall be co-extensive with their time in the Bar council of India:.

(2) (i) Every State Council shall have an Advocate Welfare Committee known as Bar Council of India Advocates Welfare Committee for the State.

(ii) The Committee shall consist of member Bar Council, of India from the State concerned. who shall be the Ex-Officio Charmin of the Committee and two mem hers elected from amongst the members.

(iii) The Secretary of the State Bar Council concerned will act.as Ex-Officio Secretary of the Committee.

(iv) The term of the member, Bar Couricil of India in the Committee shall be co-extensive with his term in the 'Bar Council of India.

(v) The term of members elected from the State Bar Council shall be two years.

(vi) Two members of the Committee will form a quorum of any meeting of the Committee.

(3) Every State Bar Council shall open an account in the name of the Bar Council of India Welfare Committee for the State, in any Nationalised Bank.

(4) No amount shall be withdrawn from the Bank unless that cheque is signed by the Chairman of the Welfare Committee and its Secretary.

(5) The State Bar Council shall implement Welfare Schemes approved by the Bar Council of India through Advocates Welfare Committee as constituted under sub-clause (2) (i). The State Bar Councils may suggest suitable modifications in the Welfare Schemes or suggest more schemes, but such modifications or such suggested schemes shall have effect only after approval by the Bar Council of India.

(6) The State Bar Council shall maintain separate account in respect of the Advocate Wel fare Fund which shall be audited annually along with pthey accounts of the State Bar Council and send the same along with Auditors Report to the Bar Council of India.

44B The Bar Council of India shall utilise the funds received under Rule 41 (2) in accordance with the schemes which may be framed from time to time.

Section V-Duty imparting training

45. It is improper for an Advocate to demand or accept fees or any premium from any person as a consideration for imparting training in law under the rules prescribed by a State Bar Council to enable such portion to qualify for enrolment under the Advocates Act, 1961.

Section VI-Duty to- Render Legal Aid ,

46. Every Advocate shall in the practice of the profession of law bear in mind that anyone genuinely in need of a lawyer is entnea to legal assistance even though he cannot pay for it fully or adequately and that within the limits of an Adocate's economic condition, free legal assistance to the indigent and oppressed is one of the highest obligations an Advocate owes to society.

47 An Advocate shall not personally engage in any business but he may be sleeping partner in a firm doing business provided that, in the opinion of the appropriate State Bar Council, the nature of the business is not inconsistent with the dignity of the profession.

48. An Advocate may be Director or Chairman of the Board of Directors of a company with or without any ordinary sitting fee, provided none of his duties are of an executive character, an advocate shall not be a Managing Director or a Secretary of any company.

49 An Advocate shall not be a full time salaried employee of any person, government, firm, corporation or concern, so long as the continues to practice, and shall, on taking up any such employment, intimate the fact to the Bar Council on whose roll his name appears, and shall thereupon cease to practice as an advocate so long as he continues in such employment.

Nothing in this rule shall apply to a Law Officer of the Central government of a State or of any Public Corporation or body with Section 24(1) (e) of the Act despite his being a full time salaried employee.

Nothing in this rule shall apply to a Law Officer of the Central government of a State or of any Public Corporation or body constituted by statue who is entitled to be enrolled under that rules of his State Bar Council made under Section 28(2) (d) read with Section 24 (1) (e) of the Act despite his being a full time salaried employee.

Law Officer for the purpose of this rule means a person who is so designated by the terms of his appointment and who, by the said terms, is requirea to act and/or plead in Courts on behalf of his employer.

50 An Advocate who has inherited, or succeeded by survivorship to, a family business may continue it, but may not personally participate in the management thereof.

51. An Advocate may review Parliamentry bills for a remuneration, edit leagal text books at a salary, do press vetting for newspapers, coach pupils for legal examination, set and examine question papers and subject to the rules against advertising and full time employement, engage in broad casting journalism, lecturing and teaching subjects, both legal and not legal.

52.Nothing in these rules shall prevent an Advocate from accepting, after obtaining the consent of the State Bar Council part time imployment provided that in the opinion of the State Bar Counicl the nature of the employment does not conflict with his professional work and is not inconsistent with the dignity of the profession this rule shall be subject to such directives if any as may be issued by the Bar Council of India from time to time.

CHAPTER-III
(Condition for right to practice)
(Rules under Section 49 (1) (ah) of the Act.

Even Advocate shall be under an obligation to see that his name appears on the roll of the State Council within whose jurisdiction he ordinary practices.

PROVIDED that if an advocate does not apply for transfer of his name to the roll of the State Bar Council within whose jurisdiction he is ordinarily practising within six months of the start of such practice it shall be Deemed that he is guilty of professional misconduct within the meaning of section 35 of the Advocates Act".

2 An Advocate shall not enter into a partnership or any other arrangement for sharing remuneration with any person or legal practitioner who is not an advocate.

3 Every Advocate shall keep informed the bar council on the roll of which his name stands, of every change of his address.

4. The council or a state council can call upon an advocate to furnish the name of the state council on the roll of which his name is entered and call for other particulars.

5. (1) An Advocate who voluntarily suspends his practice for any reason whatsoever, shall intimate by registered post to the state bar council on the roll of which his name is entered, of such suspension together with his certificate of enrolment in original.

(2) whenever any such advocate who has suspended his practice desire to resume his practice, he shall apply to the secretary of the state bar council for resumption of practice, along with an affidavit stating whether he has incurred any of the disqualifications under section 24A, chapter III of the Act during the period of suspension.

(3) The Enrolment committee of the state bar council may order the resumption of his practice and return the certificate to his with necessary endorsement. If the Enrolment Committee is of the view that Advocates has incurred any of the disqualifications the committee shall refer the matter under proviso to Section 26(1) of the Act.

(4) On suspension and resumption of practice the secretary shall act in terms of rule 24 of part IX.

6. (1) An Advocate whose name has been removed by order of the supreme Court or a High Court or the Bar Council as the case may be, shall not be entitled to practice the profession of law either before the court and authorities mentioned under section 30 of the Act, or in chambers, or otherwise.

(2) An Advocate who is under suspension shall be under same disability during the period of such suspension as an

Advocate whose name has been removed from the roll.

7. An officer after his retirement or otherwise ceasing to be in service shall not practice for a period of two years in the area in which he exercised jurisdiction to one in which he held office.

RESOLVED that nothing in these Rules shall prevent any such person from practicing in any Court or tribunal or authority of superior jurisdiction to one in which he held office.

Explanation: 'Officer' shall include a judicial officer or authority as referred to in section 30 of Act.

'Area' shall mean area in which the person concerned exercising jurisdiction.

8. No Advocate shall be entitled to practice if in the opinion of the council he is suffering from such contagious disease as makes the practice of law a hazard to the health of others. This disqualification shall last for such period as the Council directs from time to time

CHAPTER-IV

FROM OF DRESSES OR ROBES TO BE WORN BY ADVOCATES

(Rules under section 49 (1) of the Act)

Advocates appearing in the Supreme Court, High Court, Subordinate Courts, Tribunals or Authorities shall wear the following as part of their dress which shall be sober and dignified:-

ADVOCATES OTHER THAN LADY ADVOCATES

(a) a black buttoned up coat, chapkan, achkan black sherwani and white bands with Advocates' Gowns, or

(b) a block open breast coat, white shirt, white collar, stiff or soft, and white bands with Advocate's Gowns.

In either case long trousers (white, black striped of grey) or Dhoti.

I. LADY ADVOCATES

(a) Black and full or half sleeve jacket or blouse, white collar stiff or soft, with white bands and Advocates' Gowns.

White blouse, with or without collar, with white bands and with a black open breast coat.

OR

(b) Sarees or long skirts (White or black or any mellow or subdued color without any print or design) or Flare (White, black or black striped or grey) or Punjabi dress churidar-kurta or salwar-kurta with or without dupatta) white or black.

Provided that the wearing of Advocates' gown shall be optional except when appearing in the supreme Court in High Court.[Provided further that in courts other than the supreme Court, High Court District Court, Sessions Court or city Civil Court a black tie may be worn instead of bands.]

Bar Council of Uttarakhand, Nainital-263001 Registration fee Details Registration of Candidate on the Rolls of Bar Council of Uttarakhand Year 202..... Category-SC/ST/Other ( ) Office Copy All fee Payable to SBI (High Court) IFSC Code- SBIN220010634	Bar Council of Uttarakhand, Nainital-263001 Registration fee Details Registration of Candidate on the Rolls of Bar Council of Uttarakhand Year 202..... Category-SC/ST/Other ( ) Applicant Copy All fee Payable to SBI (High Court) IFSC Code- SBIN220010634	Bar Council of Uttarakhand, Nainital-263001 Registration fee Details Registration of Candidate on the Rolls of Bar Council of Uttarakhand Year 202..... Category-SC/ST/Other ( ) Bank Copy All fee Payable to SBI (High Court) IFSC Code- SBIN220010634
Bar Council of Uttarakhand A/C No:- 30612293272 Amount:- Rs. ..... Amount in Words-	Bar Council of Uttarakhand A/C No:- 30612293272 Amount:- Rs. ..... Amount in Words-	Bar Council of Uttarakhand A/C No:- 30612293272 Amount:- Rs. ..... Amount in Words-
Bar Council of India Collection Fund A/C No:- 30602947546 Amount:- Rs. ..... Amount in Words-	Bar Council of India Collection Fund A/C No:- 30602947546 Amount:- Rs. ..... Amount in Words-	Bar Council of India Collection Fund A/C No:- 30602947546 Amount:- Rs. ..... Amount in Words-
Total Amount of Fee Rs.	Total Amount of Fee Rs.	Total Amount of Fee Rs. .....
Date of Fee Deposition:- Name of the Applicant- Fathers Name- Address- Contact No.	Date of Fee Deposition:- Name of the Applicant- Fathers Name- Address- Contact No.	Date of Fee Deposition:- Name of the Applicant- Fathers Name- Address- Contact No.
To be filed by the bank Bank Name & Branch Branch Code Deposit Date- Stamp Authorised	To be filed by the bank Bank Name & Branch Branch Code Deposit Date- Stamp Authorised	To be filed by the bank Bank Name & Branch Branch Code Deposit Date- Stamp Authorised
Journal No.	Journal No.	Journal No.